

विधानसभा सत्र

प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हो रहा है। 21 दिसम्बर तक चलने वाले सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज तपोवन विधानसभा परिसर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को कुल 3 सौ 16 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें विधानसभा सदस्यों द्वारा 2 सौ 48 तारांकित और 68 अतारांकित प्रश्न सदन में उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार शीतकालीन सत्र की चार बैठकों के दौरान विभिन्न नियमों के तहत सदन में सदस्यों द्वारा चर्चा भी की जाएगी। इनमें नियम 62 के तहत 5, नियम 63 के तहत एक, नियम 101 के तहत 5 और नियम 130 के तहत तीन विषयों पर सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा सदन में 15 बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर चर्चा होने के बाद उन्हें पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार सत्र में हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार जीरो आवर की शुरुआत की गई है। इसके तहत रोजाना सत्र के दौरान 12 से साढ़े 12 बजे तक कोई भी सदस्य प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकते हैं।

सर्वदलीय बैठक

इस बीच विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज धर्मशाला के तपोवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया था। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक सुखराम चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी दी।

मुख्यमंत्री

राज्य सरकार द्वारा एचपीएमसी की नियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता को पिछले दो वर्षों के दौरान दोगुना किया गया है। राज्य में 7 सीए स्टोर में कुल भंडारण क्षमता वर्ष 2023 से पहले 3 हजार 3 सौ 80 मीट्रिक टन थी जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8 हजार 2 सौ 60 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सीए स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को एक सौ 50 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान भी जारी किए हैं।

ऑपरेशन क्लीन

शिमला जिला में नशे के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया है। इसके तहत हर रोज पुलिस नशा तस्करो को गिरफ्तार कर रही है इस साल अब तक पुलिस ने 13 सौ लोगों को नशा तस्करी करने पर गिरफ्तार किया है। वर्ष 2023-24 में पुलिस ने साढ़े 6 किलोग्राम चिट्ठा और हीरोइन सीज की है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया क बीते दिनों शिमला पुलिस ने जिला में 9 नशा तस्करो को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शिमला जिला को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए पुलिस युद्धस्तर पर कार्य कर रही है।

कैलेण्डर

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि वर्ष-2025 के सरकारी कैलेण्डर 26 दिसम्बर से आम लोगों को विक्रय किए जाएंगे। कैलेण्डर की कीमत 20 रुपये निर्धारित की गई है।